viuh ckr

भारत में चीन की घुसपैठ अस्वीकार

लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी एरिया से चीनी सैनिकों की वापसी के बाद भारत को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। चीनी सैनिकों ने १५ अप्रैल को भारतीय सीमा में घुसपैठ की और १६ कि.मी. अंदर तक अपने तम्बू गाड़ दिए। बाद में ५ मई को उन्होंने अपने तम्बू उखाड़े। लगभग तीन सप्ताह बाद वे वापस नहीं लौटे होते तो भारत का लगभग ७५० वर्ग किमी. नया क्षेत्र चीन के कब्जे में चला जाता। पहले ही चीन भारत के लगभग १ लाख वर्ग मील भूभाग को दबाये हुए है।

अप्रैल-मई २०१३ की दौलत बेग ओल्डी एरिया में चीन की घुसपैठ ने १९६२ की याद ताजा कर दी है। उन दिनों ''हिन्दी-चीनी भाई-भाई'' के नारे लग रहे थे। चीन के साथ भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसके पूर्व चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिशद में चीन को स्थाई स्थान दिलाने में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की मदद की थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू चीन की प्रशंसा में बढ़ चढ़कर बोल रहे थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ?

परिणाम हुआ १९६२ में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण। पंडित नेहरू ने इसे भारत के साथ धोखा कहा। चीन के साथ एक मंच पर शांति के कबूतर उड़ाने वाले पंडित नेहरू की कूटनीतिक पराजय से पूरा भारत अपमानित हो गया। भारतीय संसद ने अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव में संकल्प लिया कि वह चीन से भारतीय भूभाग को पूरी तरह मुक्त करायेगी।

चीन भारत के कई इलाकों को अपना भूभाग खुलेआम बता रहा है। चीन के नक्शे में कई भारतीय भूभाग बताए जा रहे हैं। इस बार भी चीन यह कहते हुए ही दौलत बेग ओल्डी एरिया से वापस लौटा है कि यह पूरा एरिया चीन का है। चीन की हठधर्मिता के कारण इस मामले में कई बार फ्लैग मीटिंग, जिसमें दोनों ओर के सैनिक अधिकारी शामिल थे, विफल हो गई। और अंततः चीन यह संदेश देकर वापस लौटा है कि वह स्वेच्छा से अपने इलाके में आया था और स्वेच्छा से ही वापस जा रहा है। इसका निहितार्थ है कि चीन स्वेच्छा से वापस आ भी सकता है।

वास्तव में समस्या की जड़ है तिब्बत की गुलामी। तिब्बत १९५९ तक स्वतंत्र देश था। भारत और चीन के बीच था स्वतंत्र तिब्बत। चीन के साथ नहीं, बल्कि तिब्बत के साथ भारत की सीमा जुड़ी थी। आज भी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) का अस्तित्व इसी का प्रमाण है।

भारत एवं चीन की सीमा आपस में तिब्बत की गुलामी के बाद मिली है। तिब्बत पर चीन ने अपना अवैध नियंत्रण किया और भारत की सीमा पर आ गया। भारत और चीन के बीच लड़ाई भी १९६२ में तभी हुई। दोनों के बीच पहले युद्ध नहीं हुए थे। भारत एवं चीन के बीच संबंधों को सुधारने का एकमात्र उपाय है कि फिर से तिब्बत को भारत एवं चीन के बीच बफर स्टेट (मध्यस्थ राज्य) बनाया जाये। अर्थात् चीन से भारत की सुरक्षा के लिए चीन से तिब्बत की आजादी बेहद जरूरी है।

तिब्बत समर्थक इसीलिए कह रहे हैं कि तिब्बत की समस्या का समाधान विश्वशांति के लिए और विशेषकर भारत की सुरक्षा तथा एकता-अखंडता के लिए जरूरी है। चीन सरकार द्वारा तिब्बत में उत्पीड़न जारी है। इस ओर विश्व समुदाय का ध्यान खींचने के लिए गत कुछ माह में ही लगभग डेढ़ सौ तिब्बती आंदोलनकारी आत्मदाह के जरिये विचलित करने वाले बलिदान कर चुके हैं। भारत को चाहिए कि वह तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन के सवाल को सभी उपयुक्त मंचों पर उठाये तथा साम्राज्यवादी चीन को बेनकाब करे।

भारत और चीन के बीच शीर्षस्थ राजनेताओं तथा राजनयिकों एवं अन्य उच्चपदस्थ अधिकारियों के बीच संवाद-प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। शिष्टमंडलों एवं विशेषज्ञ दलों का स्वागत दोनों देश जरूर करते रहें। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंध सुधारने के उपाय करते रहें। ये सारी बातें जरूरी भी हैं और सराहनीय भी। लेकिन इनसे भी बढ़कर जरूरी है भारत के स्वाभिमान तथा एकता-अखंडता की सुरक्षा। भारतीय संसद के १४ नवंबर १९६२ के सर्वसम्मत प्रस्ताव का क्रियान्वयन। चीन के कब्जे से भारतीय भूभाग को खाली कराना भारत का संवैधानिक तथा नैतिक कर्तव्य है।

इस मामले में सभी तिब्बत समर्थक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी ध्यान में रखना होगा। उनका संघर्ष भारत के हित में है। चीन से संबंध सुधारने के नाम पर हम जब तक तिब्बत के हितों की बलि चढ़ाते रहेंगे, तब तक चीन के हाथों भारत को अपमानित-पराजित होना पड़ेगा। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र के लोग तो चीन के साथ सैनिक समाधान के भी पक्ष में हैं। उन लोगों का मत है कि भारत की स्थिति अब १९६२ वाली नहीं है। भारत की सामरिक तैयारी से चीन भलीभाँति परिचित है। असल कारण यही है कि चीन को दौलत बेग ओल्डी एरिया से वापस लौटने को बाध्य होना पड़ा है। इसलिए चीन के मुकाबले भारतीय सामरिक तैयारी बेहतर रहनी चाहिए।

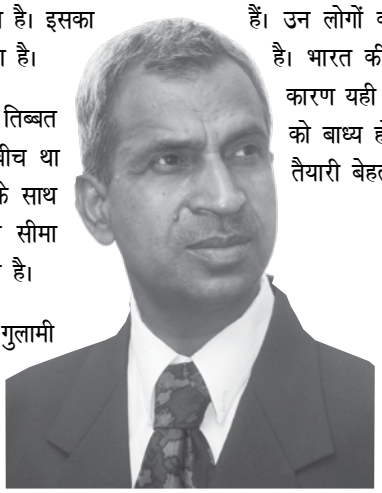

प्रो० श्यामनाथ मिश्रा
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राज.)
E-mail :- shyamnathji@gmail.com

तिब्बत में एक और आत्मदाह, 118 तक पहुंची संख्या

(फायूल, २६ मई, २०१३)

एक तिब्बती व्यक्ति ने तिब्बत में चीनी कब्जे और कठोर नीतियों के विरोध में पूर्वी तिब्बत के अड्रिल इलाके में खुद को आग लगा लिया। ३१ वर्षीय तेनजिन शेराब ने २७ मई को आत्मदाह के साथ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। दक्षिण भारत में रहने वाले एक भिक्षु जम्पा योनतेन ने बताया कि शेराब के निधन के बाद ही उनके परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उनके आत्मदाह की जानकारी हो पाई। योनतेन ने बताया, "विरोध प्रदर्शन के बाद चुमार से चीनी सुरक्षा कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने तेनजिन शेराब के शव को अपने कब्जे में ले लिया। अगले दिन २८ मई को उनका शव उनके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया।

आत्मदाह से पहले कुछ दिनों में तेनजिन शेराब अपने दोस्तों से चीन सरकार की खराब नीतियों के बारे में बात करते थे और विलुप्त होने की ओर बढ़ रहे तिब्बती धर्म और संस्कृति को लेकर चिंता जताते थे। तेनजिन शेराब ने अपने दोस्तों से कहा था, "हम अब चीन के लगातार प्रताड़ना और दमन के बीच ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते।"

तेनजिन शेराब, के. धोनढुप और छोमे के पुत्र थे और पांच भाई-बहनों में वह सबसे बड़े थे। वर्ष २००६ से अब तक चीन के शासन के तहत रहने वाले ११८ तिब्बतियों ने खुद को आग लगा लिया है। आत्मदाह के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने वाले इन सभी लोगों की मांग थी कि परमपावन दलाई लामा को निर्वासन से वापस लाया जाए और तिब्बतियों को स्वाधीनता दी जाए।

चीन सरकार ने इन आत्मदाह के जवाब में और कठोर नीतियां अपनाई हैं, आत्मदाह द्वारा विरोध प्रदर्शन को आपराधिक कार्रवाई बताई जाती है और बहुत से लोगों को कथित रूप से आत्मदाह विरोध प्रदर्शन में सहयोग के लिए "जानबूझकर नरहत्या" जैसे गंभीर आरोप लगाकर जेल की कठोर सजा दे दी गई है। चीनी अधिकारियों ने तिब्बतियों को आत्मदाह करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने और उनके परिवार के साथ शोक संवेदना जताने से भी रोक दिया है और यह घोषणा की गई है कि जिन गांवों में आत्मदाह की घटनाएं होंगी वहां के विकास फंड को रोक दिया जाएगा।

नेपाल की भारतीय सीमा तक चीनी रेल लाइन लाने की कोशिश

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, २० मई, २०१३)

नेपाल सरकार के अनुरोध पर चीन इस संभावना पर अध्ययन कर रहा है कि ल्हासा-शिगास्ते रेल मार्ग को बढ़ाकर तिब्बत के नेपाल सीमा पर स्थित कस्बे ड्रैम तक ले जाया जाए। ल्हासा-शिगास्ते रेल मार्ग २०१५ तक बनकर पूरा होना है। माइरिपब्लिका डॉट कॉम (नेपाल) की १८ मई की खबर में बताया गया है कि चीन के दौर पर कुछ नेपाली पत्रकारों को चीनी स्टेट कौंसिल सूचना कार्यालय में उप मंत्री सुश्री कुई युयिंग ने यह आश्वासन दिया। खबर में बताया गया है कि कुछ नेपाल नेता तो इस लाइन को बढ़ाकर भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुंबिनी तक ले जाना चाहते हैं। उनका मानना है कि ऐसे रेलमार्ग से भारत, नेपाल और चीन के बीच व्यापार बढ़ेगा। लुंबिनी में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चीन सरकार के द्वारा प्रवर्तित एक एनजीओ वहां एक भारी पर्यटन विकास प्रोजेक्ट चला रहा है। करीब २.१ अरब डॉलर की लागत से बन रहा ल्हासा-शिगास्ते रेलमार्ग क्विंघई-तिब्बत-ल्हासा रेलमार्ग का विस्तार है। इस रेलमार्ग पर कुल १३ स्टेशन होंगे। नेपाल-तिब्बत सीमा पर स्थित सबसे नजदीकी कस्बे तातोपानी से शिगास्ते करीब ३६२ किलोमीटर दूर है। सिंधुपलचोक जिले में तातोपानी और केरुंग जिले में रसुआ कस्बा शिगास्ते से सबसे नजदीकी सीमावर्ती केंद्र हैं।

कुछ चीनी मीडिया खबरों में पहले यह कहा जा रहा था कि ल्हासा-शिगास्ते रेलमार्ग को भारतीय राज्य सिक्किम के पास स्थित तिब्बती सीमावर्ती कस्बे ड्रोमो तक ले जाने की योजना है।

2012 में तिब्बत में धार्मिक दमन और बढ़ा: अमेरिकी रिपोर्ट

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, २२ मई)

अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने गत २० मई को विदेश मंत्रालय की २०१२ की वार्षिक वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने "खासकर मुस्लिम उइगर समुदाय और तिब. बती बौद्धों का काफी सख्ती से दमन किया है और तिब्बती मठों पर गहरी नजर रखी जा रही है।" रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष २०१२ में चीन और ईरान में धार्मिक आज़ादी देने से इनकार किया गया है और इस मामले में छह अन्य देशों-इरिट्रिया, बर्मा, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब, सूडान और उजबेकिस्तान की स्थिति भी "खासी चिंताजनक है।"

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी इस रिपोर्ट के सारांश में कहा गया है: "तिब्बती इलाके में लंबे समय से जारी ज्यादा दमनकारी सरकारी कार्रवाई और धार्मिक नीतियों की प्रतिक्रिया में तिब्बती भिक्षु, भिक्षुणी और आम व्यक्ति लगातार अक्सर किसी मठ में या उसके आसपास आत्मदाह के द्वारा अपना असंतोष और विराध जता रहे हैं जिसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। चीन सरकार के इन दमनात्मक कार्रवाइयों में मठों और ननरी में गहन आधिकारिक कार्रवाई जिससे लोगों के जान चले जाने तक की घटनाएं होती हैं, लोगों की मनमाने तरीके से गिरफ्तारी और प्रताड़ना शामिल होता है। वर्ष २०१२ में आत्मदाह की ८३ घटनाएं हुई हैं।"

फर्स्ट पोस्ट डॉट कॉम की २१ मई की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री केरी ने वचन दिया कि वे प्रतिबंधात्मक देशों से कहेंगे कि वे लोगों को ज्यादा अधिकार दें, भले ही वे अमेरिका के सहयोगी देश हों और भले ही वे असुविधा महसूस करें। इस रिपोर्ट में तिब्बती इलाके में स्थिति के बारे में कहा गया है: "पूरे साल गंभीर दमन हुआ है, लेकिन राजनीतिक रूप से संवदेनशील और धार्मिक वर्षगांठों एवं आयोजनों के दौरान यह और भी सख्त हो जाता है। तिब्बती बौद्ध परंपराओं के पालन में सरकारी दखल से लोगों में भारी असंतोष है। पूरे साल के दौरान तिब्बतियों के आत्मदाह की घटनाएं बढ़ती गई हैं।"

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी राजदूत सुजान जॉनसन कुक ने कहा, "वर्ष २०१२ में चीनी नीतियों के विरोध में ८३ तिब्बतियों ने आत्मदाह किए हैं। अब आत्मदाह करने वालों की कुल संख्या १०० से ज्यादा हो चुकी है।" उन्होंने स्थितियों में बदलाव लाने के लिए अप्रैल २०१३ में चीन की यात्रा की थी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के खिलाफ व्यापक तौर पर भेदभाव किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, "बहुत से तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं और ननों ने यह बताया है कि वे चीन के दूसरे हिस्सों में जाते समय अपने मठ के लबादे की जगह सामान्य नागरिकों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े पहनते हैं ताकि किसी तरह के भेदभाव या पुलिस द्वारा मनमाने तरीके से जांच से बचा जा सके।"

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अमेरिकी सरकार ने लगातार चीनी प्रशासन से कई स्तरों पर यह अनुरोध किया है कि वे सभी धर्मों के धार्मिक आज़ादी का सम्मान करें और तिब्बतियों को अपनी धार्मिक परंपरा के संरक्षण, पालन, शिक्षण और विकास की इजाजत दें। चीन सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह दलाई लामा और उनके प्रतिनिधियों के साथ रचनात्मक संवाद करे और उन नीतियों को बदले जिनसे तिब्बत की विशिष्ट धार्मिक सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को खतरा उत्पन्न हो रहा है और जो तिब्बतियों के बीच अंसतोष की प्रा. थमिक वजह है।"

तिब्बती नेताओं ने अमेरिका से अनुरोध किया कि वह चीन को वार्ता शुरू करने के लिए मनाए

(आईएएनएस, धर्मशाला, ७ मई, २०१३)

निर्वासित तिब्बती प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि वह चीन को इस बात के लिए मनाए कि वह तिब्बत मसले पर वार्ता फिर से शुरू करे। यह देखते हुए कि पिछले चार वर्ष में ११७ तिब्बतियों ने खुद को आग के हवाले कर दिया है।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक दलाई लामा के राजनीतिक उत्तराधिकारी डॉ. सांग ने कहा, "मैं अमेरिकी कांग्रेस से अनुरोध करता हूं कि वह अपने प्रयास और मजबूत करते हुए चीन सरकार को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे कि वह तिब्बत मसले के शांतिपूर्ण तरीके से हल के लिए एक सार्थक वार्ता करे।" सांगे ने कहा, "यदि कांग्रेस की विदेश नीति समिति तिब्बत पर सुनवाई आयोजित करे तो इससे काफी मदद मिलेगी।"

उनके अनुसार मार्च २००६ से अब तक ११७ तिब्बतियों ने खुद को आग लगा लिया है। इन सभी आत्मदाह करने वाले लोगों की साझी पुकार यही रही है कि आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को तिब्बत में वापस लाया जाए और तिब्बतियों को स्वाधीनता मिले।

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक आज़ादी पर अमेरिकी आयोग की सालाना रिपोर्ट का हवाला देते हुए सांगे ने कहा, "तिब्बतियों को यह मानने की हर वजह है कि चीन असल में तिब्बत को चाहता है, तिब्बतियों को नहीं।"

अप्रैल, २०१३ की आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बती इलाके में धार्मिक आज़ादी की स्थिति पिछले एक दशक में अब तक सबसे ज्यादा खराब है। सांगे ने कहा कि कांग्रेस के सदस्यों ने पिछले वर्षों में तिब्बत की मदद के लिए कई कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा, "इससे मध्यम मार्ग नीति के द्वारा तिब्बत समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिए दलाई लामा की दृष्टि को राजनीतिक, नैतिक और वित्तीय समर्थन हासिल हुआ है। मध्यम मार्ग नीति में कहा गया है कि चीन के संविधान के ढांचे के भीतर ही तिब्बत को वाजिब स्वायत्तता दी जाए।"

सीटीए के एक प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया कि तिब्बत मसले को हल करने के प्रयास के तहत चीन और दलाई लामा के दूतों के बीच वर्ष २००२ से नौ दौर की वार्ता हो चुकी है। पिछले नौवें दौर की वार्ता बीजिंग में जनवरी २०१० में हुई थी, लेकिन इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है।

नजरबंदी से रिहा हुए नेत्रहीन आंदोलनकारी ने कहा कि चीन भरोसे के लायक नहीं

(कौंतेय सिन्हा, टीएनएन, लंदन, २३ मई)

चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग के हाल में नई दिल्ली दौरे के बाद भारत में माहौल "हिंदी-चीनी भाई-भाई" जैसा हो सकता है, लेकिन चीन के सबसे वांछित व्यक्ति छेन गुआंगछेंग ने भारत को सख्त शब्दों में सचेत रहने की चेतावनी दी है। एक नेत्रहीन आंदोलनकारी छेन तब से एक अंतरराष्ट्रीय हीरो बन गए हैं, जब से वे बीजिंग में नजरबंदी से भाग कर बाहर आने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। उन्होंने चीन में जबरन गर्भ गिराने और बधियाकरण को उजागर किया था जिसकी वजह से उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। एक दिन वह चीन से भाग निकले और उन्होंने अमेरिका में शरण ली। टीओआई को दिए एक दुर्लभ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि, "चीन सरकार का भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन के लोग इस तरह के नहीं है, लेकिन वहां की सरकार की बातों का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वह एक एकाधिकारवादी शासन है।"

सूचनाओं के स्वतंत्र प्रवाह को दबाने का चीन के सख्त कदमों का सीधे अनुभव करने वाले छेन ने टीओआई से कहा कि वह दलाई लामा का तहे दिल से समर्थन करता है। चीन ने हाल में तिब्बती नेता के खिलाफ कठोर रवैया अपनाते हुए उनसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से नाराजगी दिखाते हुए उनके प्रति ठंडा रुख दिखाया। आखिरकार कैमरन को अपनी चीन यात्रा रद्द करनी पड़ी क्योंकि "चीन सरकार को उनसे मिलने का समय नहीं था।"

छेन बचपन से ही नेत्रहीन हैं और २००६ में उन्हें कैद कर दिया गया जिसमें उन्होंने करीब ४ साल गुजारे। उन्होंने टीओआई से कहा, "तिब्बतियों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। मैं चीन और दलाई लामा के बीच वार्ता का पूरी तरह समर्थक हूं। चीन दलाई लामा को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करता है। यह महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय चीन सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाएं कि वह तिब्बत को स्वाधीन करे। छेन अपनी कहानी बताने के लिए भारत आने के इच्छुक हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा अंतःकरण के कैदी घोषित किए गए छेन ने कहा, "यह दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों के हित में है कि भारत, चीन में ज्यादा पारदर्शिता की मांग कर आंदोलनकारियों के समर्थन में आवाज उठाए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय यदि कुछ नहीं बोलता है तो चीन सरकार अपने लोगों को पीड़ित करने का रवैया जारी रखेगी।"

छेन फिलहाल अमेरिका में रह रहे हैं जहां वह मानवाधिकारों के मसले पर आवाज उठाते रहते हैं। छेन को अब अपने परिवार और दोस्तों के सुरक्षा की चिंता सता रही है। उनके बड़े भाई छेन गुआंगफू को कैद में रखा गया है। बताया जाता है कि चीनी प्रशासन ने कुछ गुंडों की सेवाएं ली थीं जिन्होंने छेन की पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी बायीं आंख के पास एक हड्डी टूट गई और इसके बाद उन्हें चिकित्सीय उपचार की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। उन्होंने छेन के मां की भी पिटाई की।

छेन ने बताय कि हर दिन उनके बेटी की तीन लोग पीछा करते रहते हैं और उन्होंने उसके स्कूल बैग की भी तलाशी ली है।

उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की बहुत चिंता सता रही है। उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी युआन वीजिंब और उनकी युवा बेटी से "बदला" लिया जा सकता है।

लगातार दूसरे साल भी चीन सरकार और दलाई लामा के बीच किसी तरह की वार्ता नहीं हुई है। यह पिछले दशक में वार्ता के बीच सबसे लंबा अंतराल है। दूसरी तरफ चीन ने आरोप लगाया है कि दलाई लामा लोगों को आत्मदाह के लिए उकसा रहे हैं। वर्ष २०१२ में तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह की घटनाएं बढ़ी हैं और पूरे वर्ष मुख्य भूमि चीन में ऐसे ८२ प्रयास हुए हैं। इनमें से कम से कम ६६ घटनाओं में लोगों की जान चली गई है। ब्रिटेन ने हाल में चीन से कहा था कि वह तिब्बत के भविष्य पर दलाई लामा से अपने मतभेद को दूर करने के लिए वार्ता फिर से शुरू करे।

टीओआई से बात करते हुए ब्रिटेन के विदेश सचिव विलियम हाग ने कहा, "जहां तक मानवाधिकार की बात है, चीन लगातार एक चिंताजनक देश बना हुआ है जहां तिब्बतियों के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। दलाई लामा और चीन के बीच संवाद इस परिस्थिति से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका है।"

राजनीतिक रूप से भारत और ज्यादा कर सकता है: लोबसांग सांगे

(मन्नन कुमार, डीएनए 22 मई, 2013)

अमेरिका और यूरोप की यात्रा से हाल में ही लौटे तिब्बती प्रधानमंत्री (निर्वासित सरकार के) लोबसांग सांगे ने डीएनए से एक खास मुलाकात में इस बारे में खुलकर बात की कि तिब्बत मसले पर भारत और चीन के रवैए में बदलाव से इस पूरे इलाके में शांति कायम रखने में योगदान किस तरह से हो सकता है। पेश है उनकी बातचीत के संपादित अंशः

phuh i/kkuea=h dk Hkkjr nkSjk fdruk egRoiw.kZ g

प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने दौरे के लिए पहले देश के रूप में भारत का चुनाव करने वाले ली केचियांग तिब्बत मसले को हल करने के लिए एक सार्थक वार्ता की शुरुआत कर सकते थे। भारत और चीन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं और हम दोनों देशों में रिश्ता बेहतर रहने की कामना करते हैं। लेकिन तिब्बत मसले को हल करने से शांतिपूर्ण सीमाओं के लिए एक बफर जोन भी उपलब्ध होगा। इससे चीन सरकार के प्रति संदेह और कम होगा। तिब्बत इस इलाके में शांति कायम रखने में योगदान कर सकता है।

D;k vki okLro esa ;g ekurs gSa fd frCcr 'kkafr dk;e j[kus esa ;ksxnku dj ldrk g

जी हां, यदि तिब्बतियों को स्वायत्तता दी जाए तो। मुझे लगता है कि इस समय तो हमने वह अवसर गंवा दिया है।

phu vkSj Hkkjr ds chp tks l{;Dr c;ku tkjh gqvk mlesa ,d phu ij Hkkjr ds leFkZu dk dksbZ mYYks[k ugha gSA blds eryc vki D;k le>rs gS

यह भारत सरकार को तय करना है। हमारी तो यही कामना है कि तात्विक चर्चा हुई हो और उसमें मुख्य मसलों में तिब्बत भी एक रहा हो। भारत की सुरक्षा तिब्बत

के मसले से जुड़ी है।

D;k vki ;g ekurs gSa fd frCcr dk elyk ij fiNyk n'kd esa Hkkjr ljdkj us okftc i;kl fd, gSa\

अन्य देशों की तुलना में भारत ने तिब्बतियों के लिए सबसे ज्यादा किया है, जिसके लिए हम कृतज्ञ हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से, हमारी कामना है कि भारत और भी कुछ करे।

frCcr elys ij Hkkjr ljdkj D;k dne mBk ldrh gS\

भारत को चीन सरकार के साथ तिब्बत को मुख्य मसला बनाना चाहिए और साफ तौर से यह बताना चाहिए कि भारत की सुरक्षा तिब्बत की परिस्थिति से जुड़ी है। भारत और चीन के बीच कभी भी सीमा नहीं रही है, लेकिन तिब्बत और भारत के बीच हमेशा सीमा रही है। और तिब्बत के मसले को हल करे से इस इलाके में शांति बढ़ेगी।

Pkhu yxkrkj ,d lqijikoj curk tk jgk gS] D;k Hkkjr vc bruh lh/kh rjhds ls frCcr dk elyk mBk ldrk gS\

निश्चित रूप से, भारत इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उसके पास नैतिक अधिकार है। भारतीय मॉडल न केवल एशिया के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि दुनिया के लिए भी। भारत की समृद्ध विरासत, संस्कृति, अहिंसा के गांधीवादी विचार का अंतरराष्ट्रीय समुदाय में सम्मान किया जाता है।

u, phuh usr`Ro ds ckjs esa vkidh /kkj.kk D;k gS\

मैं समझता हूं कि अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि तिब्बत में उसी तरह की कठोर नीतियां जारी रखेंगे।

vki ,slk D;ksa lkprs gSa\

17वें पार्टी कांग्रेस में अल्पसंख्यक वर्ग का कम से कम एक व्यक्ति तो पोलितब्यूरो में था। लेकिन अब 18वें पार्टी कांग्रेस में अल्पसंख्यकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। केंद्रीय समिति में 200 से ज्यादा सदस्य हैं, उनमें सिर्फ 16 अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या भी घटकर 10 रह गई है। तिब्बतियों का प्रतिनिधित्व तो बहुत मामूली है, सिर्फ एक या दो। तिब्बत में आत्मदाह की 117 घटनाएं हो चुकी हैं और वे आत्मदाह करने वालों पर मुकदमा चला रहे हैं।

Pkhuh usr`Ro dh ekStwnk ih<+h ;qok gS A os vxys 20&30 lky jgus okys gSa A vkidks D;k yxrk gS] ph tsa fdruh vkxs c<+saxh\

“तिब्बत मसले को हल करने से शांतिपूर्ण सीमाओं के लिए एक बफर जोन हासिल होगा। इससे चीन सरकार के प्रति संदेह कम होगा। तिब्बत इस इलाके में शांति कायम रखने में योगदान करेगा”

सत्तारूढ़ पार्टी कितने लंबे समय तक टिकेगी, इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन हम चाहते हैं कि चीन जनवादी गणतंत्र के तहत ही हमें वास्तविक स्वायत्तता दी जाए जो चीनी संविधान के ढांचे के भीतर ही है। उम्मीद है कि चीनी नेतृत्व तिब्बत के दमन के निरर्थकता को समझेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इससे चीन के उभार पर सवाल खड़े होते हैं।

Hkkjr ds iM+kslh ns'kksa esa phu ds c<+rs fuos'k ij dbZ gydksa esa fpark trkbZ tk jgh gS\

चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल में निवेश किया है। चीन ने जिस सड़क मार्ग के निर्माण में मदद की है वह ल्हासा से लेकर नेपाल तक जाता है। उनकी योजना रेलमार्ग को भी ल्हासा से शिगास्ते होकर सिक्किम की सीमा तक ले जाने और उसके बाद उसे नेपाल और बांग्लादेश तक ले जाने की है। हमें यह देखना होगा कि इस संबंध में भारत सरकार क्या कर सकती है।

D;k vkidks yxrk gS fd Hkkjr dks lhek ds elys ij FkksM+h T;knk vkØkedrk fn[kkuh gksxh\

जी हां, सुरक्षित महसूस करने के लिए भारत को पूरे सीमा के समानांतर बुनियादी ढांचे को सुधारना होगा।

Pkhu dk ,slk c;ku vk;k gS fd Hkkjr esa jgus okys frCcrh vkRenkg ds fy, mdlk jgs gSa\

यह आरोप निराधार है और इसके लिए किसी तरह का प्रमाण नहीं है। हम उन्हें निमंत्रण देते हैं कि वे धर्मशाला में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजें और हमारे सारे रिकॉर्ड की जांच करें। तथ्य तो यह है कि हम तिब्बत में आत्मदाह को हतोत्साहित कर रहे हैं, यह हमारे दर्शन के खिलाफ है।

fQj frCcrh vkRenkg dk lgkjk D;ksa ys jgs gSa\

क्योंकि तिब्बत पर लगातार कब्जा बना हुआ है—उसका दमन हो रहा है और तिब्बतियों को आर्थिक रूप से हाशिए पर धकेला जा रहा है। चीनियों द्वारा किया जा रहे पर्यावरण के क्षरण और तिब्बतियों की नौकरियां छीन कर तिब्बत में बस रहे चीनियों द्वारा जबरन सांस्कृतिक विलोपन इसको उकसाने के लिए काफी वजहे हैं।

vesfjdk ds vius gky ds nkSjs ds ckjs esa crk,a\

मैं कांग्रेस के 21 सीनेटर से मिला, विदेश मंत्री जॉन केरी को एक पत्र लिखा, उनके चीन जाने के मुश्किल से एक महीना पहले। उन्होंने तिब्बत की मौजूदा स्थिति में रुचि दिखाई और उनसे कहा कि चीन एवं तिब्बत के बीच वार्ता को आगे बढ़ाएं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दलाई लामा ने अपने राजनीतिक अधिकार का परित्याग कर दिया है और अब तिब्बती प्रशासन एक लोकतांत्रिक ढांचा है।

ल्हासा का "आधुनिकीकरण" बंद करो, तिब्बती लेखिका ने गुहार लगाई

(साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट, ८ मई, ब्लॉग)

एमी ली

जब तिब्बती लेखिका सेरिंग वुएजर ने अपने गृह नगर ल्हासा में व्यावसायिक विकास के खिलाफ ऑनलाइन विरोध जताया तो तिब्बत के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए हजारों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया पोस्ट करते हुए और अपने विचार साझा करते हुए उनका समर्थन किया।

ज्यादातर समर्थकों का कहना है कि उन्होंने पर्यटक के रूप में तिब्बत की यात्रा की है। अन्य कई का कहना है कि उन्होंने इसे सिर्फ फिल्मों या तस्वीर में देखा है। लेकिन शायद बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि वुएजर के लिए और अन्य जगहों पर बस चुके तिब्बतियों के लिए पश्चिमी चीन के स्वायत्तशासी क्षेत्र में स्थित अपने घर तक जाना कितना कठिन है। बीजिंग में रहने वाली वुएजर जब अक्टूबर माह में अपनी मां से मिलने गई थीं तो उन्हें जिलिन जाना पड़ा था-जहां उनके हुकोउ या यात्रा परमिट को रजिस्टर्ड कराना था ताकि स्थानीय पुलिस से वह यात्रा के लिए दस्तावेज हासिल कर सकें। जब पुलिस ने यह पत्र जारी कर दिया कि वुएजर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और स्थानीय प्रशासन की मुहर लगा एक फॉर्म उन्हें मिल गया, तब ही वह जाने के लिए तैयार हो पाईं।

लेकिन वह इस दुरूह प्रक्रिया को तो बर्दाश्त कर सकती थीं, लेकिन उन सबको नहीं जो उन्होंने अपने गृह नगर में देखा। गृह नगर पहुंचकर वुएजर तिब्बत की राजधानी के प्र. ाचीन हिस्से में व्यावसायिक विकास की मात्रा और प्रकृति देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने एक याचिका के शीर्षक में लिखा, "अतिशय व्यावसायिक विकास के द्वारा ल्हासा को नष्ट किया जा रहा है।" यह याचिका तेजी से विबो नामक साइट पर फैल गई जिसके बाद इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने ब्लॉग पर इस पत्र को पोस्ट किया जिसमें उन्होंने गुहार लगाई थी, "कृपया ल्हासा को बचा लें"।

उन्होंने जिन विकास प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं उनमें शहर के पुराने इलाके में बनने वाला शॉपिंग सेंटर बारखोर मॉल शामिल है। इसके डेवलपर के मुताबिक एक बार जब यह मॉल तैयार हो जाएगा तो इसमें १,५०,००० वर्ग मीटर की जगह होगी और १,००० से ज्यादा कारों की पार्किंग के लिए जगह होगी।

वुएजर पूछती हैं कि, "इस पार्किंग को तैयार करने के लिए कितने भूमिगत जल का दोहन किया गया है?" उन्होंने इसकी याद दिलाई कि कुछ साल पहले जब एक बड़ा मॉल बनाने के लिए भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा था तब स्थानीय लोगों में कितना दर्द और असंतोष था। इस तरह का विकास करने वाली कंपनियां दो साल तक भूमिगत जल का दोहन करती रहती हैं। उन्होंने लिखा है, "लोग इससे पुराने शहर में धंसाव, मकान ढह जाने और अन्य नुकसान को लेकर चिंतित हैं।"

वुएजर उस बात को लेकर ज्यादा चिंतित है जिसे बहुत से लोग स्थानीय सरकार के तिब्बत को दूसरा "लिजियांग ओल्ड टाउन" बनाने का रवैया कहते हैं। लिजियांग युन्नान प्रांत में एक ऐतिहासिक शहर है जो अब पर्यटकों से भरा रहता है। इस शहर को बहुत ज्यादा व्यावसायिक बना देने की लगातार आलोचना की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि वहां के बहुत से मूल निवासियों के शहर छोड़ देने से अब उसकी आत्मा खत्म हो चुकी है। ल्हासा के स्थानीय लोगों को चिंता है कि लिजियांग में जो कुछ हुआ, अब वह ल्हासा में हो सकता है। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा खुलासा की गई एक योजना के मुताबिक ऐतिहासिक बारखोर इलाके में रहने वाले दुकानदारों और अन्य निवासियों को इस जगह से हटाया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक इलाका है और तीर्थयात्रियों तथा स्थानीय लोगों में काफी लोकप्रिय है। उनके मकानों और दुकानों की जगह नए बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट, बार और आर्ट गैलरी जैसी चीजें खड़ी की जा सकती हैं। इस योजना के तहत पुराने दुकानदारों को नए मॉल में और निवासियों को शहर के बाहरी हिस्से में भेजा जाएगा। इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में हर परिवार को २०,००० युआन से ३०,००० युआन तक दिया जाएगा। वुएजर ने साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट से कहा, "ल्हासा सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं है। वहां मूल रूप से रहने वाले बहुत से लोग हैं और यह एक धार्मिक स्थल भी है। आप इसे किसी सैनलिटन विलेज में नहीं बदल सकते।" सैनलिटन विलेज असल में बीजिंग का एक उच्च स्तरीय शॉपिंग सेंटर है। वुएजर ने कहा कि स्थानीय लोगों को जितना यह डर है कि इस विकास से ल्हासा का आर्किटेक्चर, संस्कृति और धर्म बदल जाएगा, वहीं उनको इसके प्रतिकार का भी डर है, लेकिन डर की वजह से वे इस योजना के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने तिब्बती भिक्षुओं द्वारा आत्मदाह के हाल के मामलों को उठाया है, लेकिन वुएजर का कहना है कि ल्हासा में ज्यादा बड़ा संकट आता दिख रहा है, लेकिन इसे काफी हद तक नजरअंदाज किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मसले पर समर्थन जुटाने के लिए बहस शुरू किया है, यह जानते हुए भी कि सरकार इस पर जवाबी कार्रवाई कर सकती है।

उन्होंने लिखा है, "इसलिए मैं यूनेस्को और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, तिब्बती विद्वानों, विशेषज्ञों और आप सबसे आग्रह करती हूं कि कृपया इस भयानक आधुनिकीकरण को रोकें जिससे ल्हासा के पुराने शहर की पर्यावरण, संस्कृति और वास्तु के प्रति अक्षम्य अपराध हो रहा है।" विबो वेबसाइट पर वुएजर के इस आग्रह वाले पत्र को सरकार द्वारा सेंसर करने से पहले उनके समर्थकों की तरफ से हजारों टिप्पणियां आई थीं।

तिब्बती लेखिका सेरिंग वुएजर

बातें हैं बातों का क्या

चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा: व्यावहारिक रुख की जरूरत

विजय क्रांति

चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान यहां की महानता के बारे में काफी कुछ कहा है जो कूटनीति में स्वाभाविक है। पर, उनकी बातों से यह अर्थ निकाल लेना कि भारत के प्रति चीन के रुख में कोई तब्दीली आ रही है, निहायत ही बचकाना होगा। दरअसल, हम भारतीय बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। जब भी कोई विदेशी राजनेता हमारे यहां आकर हमारी महान परंपराओं का बखान करता है या फिर नमस्कार जैसे लफ्ज अपनी जुबां पर लाता है तो हम गदगद हो जाते हैं। हम यह कैसे भूल सकते हैं कि द्विपक्षीय रिश्तों के मामले में हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है। चीन के प्रधानमंत्री की तरफ से भारत की तारीफ में कहे गए शब्दों से गदगद होने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि चंद दिन पहले ही चीनी सेना हमारी सीमा में घुस आई थी और १९ दिन तक जमी रही। चीन के नये प्रधानमंत्री के समर्थन में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। लेकिन क्या हम इस तथ्य को झुठला सकेंगे कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद चीनी सेना का पहला आक्रामक अभियान भारत के खिलाफ ही हुआ।

दरअसल, चीन के भीतर आंतरिक कलह बेहद चरम पर है। पर मीडिया पर नियंत्रण के चलते वहां की घटनाओं से हम बहुत कम रूबरू हो पाते हैं। चीन में सत्तारूढ़ दल के भीतर भी कई धड़े हैं। सेना के विभिन्न अंग भी आपसी धड़ेबंदी का शिकार हैं। वहां के विकास मॉडल के कारण बढ़ रही असमानता के चलते उभर रहा असंतोष पिछले कुछ वर्षों के दौरान नजर आने लगा है। व्यावसायिक उद्देश्यों के कारण लोगों से जबरन जमीनें छीनी गई हैं। इसके अलावा वहां मानवाधिकार का हनन भी आम बात है। ऐसे में जनता के भीतर नाराजगी का ज्वार लगातार उमड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से वहां लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह अलग बात है कि सरकारी मीडिया उन खबरों को बाहर नहीं आने देता। इन्हीं हालात के चलते चीन लगातार अपने पड़ोसियों के साथ बेवजह विवाद पैदा करता रहता है ताकि जनता का ध्यान आंतरिक मुद्दों से भटकाया जा सके। जापान, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, वियतनाम, रूस और भारत के साथ समय-समय पर होने वाले उसके विवाद इसका उदाहरण हैं।

इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि मौजूदा वक्त में विदेश नीति को प्रभावित करने के मामले में सबसे ज्यादा योगदान आर्थिक नीतियों का होता है। पिछले साल दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार ६६ अरब डॉलर का रहा है। लेकिन असली सच्चाई यह भी है कि भारत से किए जाने वाले आयात के मुकाबले चीन हमें २९ अरब डॉलर का ज्यादा निर्यात करता है। द्विपक्षीय व्यापार को २०१५ तक १०० अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन भारत के विरूद्ध इस असंतुलन को ठीक करने के कोई संकेत नहीं हैं।

व्यापार असंतुलन के अलावा चीन को लेकर हमारी आर्थिक नीति में भी भारी कमियां हैं। हमारे यहां से चीन को सबसे ज्यादा लौह अयस्क का निर्यात होता है। भारत के लौह अयस्क को दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाता है क्योंकि इसमें ६४ फीसदी लौह होता है। चीन इससे स्टील बनाकर न सिर्फ हमें निर्यात करता है, साथ ही विश्व बा. जार में भी वह भारतीय इस्पात कंपनियों को नहीं टिकने दे रहा है। इस तरह कच्चे माल के रूप में हमारे तरफ से होने वाले निर्यात का भी चीन भारत के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा है।

> "चीन के नये प्रधानमंत्री के समर्थन में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। लेकिन क्या हम इस तथ्य को झुठला सकेंगे कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद चीनी सेना का पहला आक्रामक अभियान भारत के खिलाफ ही हुआ"

दूसरे तैयार माल का भी हाल यह है कि हमारे यहां की कई कंपनियां अपना उत्पादन बंद करके चीन के उत्पादों का आयात कर रही हैं और फिर अपनी मुहर लगाकर बाजार में उतार देती हैं। चीन के उत्पादों ने हमारे खिलौना उद्योग को नष्ट कर दिया। रेशम उद्योग भी आखिरी सांसें गिन रहा है और यही हालत इस्पात उद्योग की है। कुछ महीने पहले अफ्रीका के कुछ देशों में चीन से आई ऐसी घटिया वाएं पकड़ी गईं जिन पर चीनी कंपनियों ने 'मेड इन इंडिया' की मुहरें लगाई हुई थीं। इसका लक्ष्य भारत की आर्थिक साख को गिराना था। ऐसे में अब बेहद जरूरी है कि हम अपनी विदेश नीति से जुड़ी आर्थिक नीतियों को भी व्यावहारिक बनाएं। व्यावहारिक का मतलब द्विपक्षीय व्यापार में कमी करना नहीं है बल्कि हमें चीन पर इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए कि वह अपने यहां भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धा का मौका दे। इसके अलावा हमें कच्चे माल की जगह तैयार उत्पाद के निर्यात

की तरफ ध्यान देना चाहिए।

रही बात दोनों देशों के बीच सीमा विवाद की तो, इस पर कोई समाधान रातों-रात नहीं निकल सकता। इस मुद्दे पर अब तक हमने दब्बूपन दिखाया है। जब चीन ने १९५१ में तिब्बत पर कब्जा किया तो हम न केवल आंख मूंदे रहे बल्कि तिब्बत पर उसके झूठे दावों का समर्थन करते रहे। तिब्बत पर कब्जे का ही प्रभाव है कि चीन तिब्बत का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकवादी और विभाजनकारी संगठनों को प्रशिक्षण देने, शरण देने और हथियार सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तिब्बत में अपनी उपस्थिति का इस्तेमाल करके आज चीन हमें पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, नेपाल, म्यांमार, और बांगलादेश के जरिये घेरने में लगा हुआ है। तिब्बत को फौजी छावनी में बदलने के अलावा वह भारतीय सीमा के साथ-साथ सड़कों का एक लंबा जाल बना चुका है। नेपाल में सड़कें बनाकर उसने प. बंगाल, बिहार और उत्तराखंड तक सीधी पहुंच बना ली है।

अब समय आ गया है कि हम अपने दब्बूपन से बाहर निकलें। तिब्बत पर कब्जे का ही नतीजा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को 'दक्षिणी तिब्बत' बताकर उस पर दावा जताने लगा है। हमारे नीति नियंताओं को यह समझ में आ जाना चाहिए तिब्बत सिर्फ दलाई लामा, मानवाधिकार और सांस्कृतिक मुद्दा नहीं है बल्कि वह भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ चुका है। अरुणाचल, असम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में उसके जमीनी दावों का सबसे कारगर जवाब यह है कि चीन को बता दिया जाए कि तिब्बत पर उसका कब्जा अवैध है इसलिए तिब्बत से जुड़े इन भारतीय इलाकों पर उसके सभी दावे बेबुनियाद और झूठे हैं। जो लोग आर्थिक रिश्तों का हवाला देकर चीन के प्रति सख्त विद्वेष नीति की मुखालफत करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि व्यापार के नाम पर देश की सुरक्षा और संप्रभुता का सौदा नहीं किया जा सकता।

तिब्बत पर नए तरह का रवैया अपनाने का समय

(सीमा सिरोही, टीएनएन, १६ मई)

हाल में भारत में चीनी घुसपैठ, इस निर्लज्जता के बाद लंबे समय तक गतिरोध, भय और गुस्से के माहौल और अचानक इसका समाधान हो जाने के पूरे प्रकरण ने एक बार फिर से पुराना सवाल उठा दिया है: तिब्बत के बारे में क्या हो? निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे ने पिछले हफ्ते वाशिंगटन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की सुरक्षा तिब्बत से सीधे जुड़ी हुई है और वह बिल्कुल सही हैं। तिब्बत के राजनीतिक उम्मीद के इस वाकपटु वाहक ने कहा, "जब चीन यह कहता है कि कई मुख्य मसलों में से तिब्बत भी एक है तो भारत के पास यह कहने के लिए ज्यादा वजह है कि भारत के लिए भी तिब्बत एक मुख्य मसला है।" पिछले वर्षों में भारत द्वारा दिखाए गए आतिथ्य के लिए काफी धन्यवाद देते हुए उन्होंने विनम्रता से भारत से यह अनुरोध किया कि वह "कुछ और" करे। सांगे को भारत की तिब्बत नीति की भस्म से जो कुछ भी जीवन के संकेत मिलते हैं उसे लेने की कोशिश करनी होगी क्योंकि वह लड़ाई को तो रोक नहीं सकते। जैसा कि उन्होंने एक बार कहा है कि तिब्बती पिछले २,००० साल से आनुवांशिक रूप से चीन से निपटने में लगे रहे हैं। लेकिन भारतीयों के लिए चीन से निपटना तुलनात्मक रूप से नई बात है, खास कर नए चीन से-ऐसा चीन जो हर जगह अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, विभिन्न तरह की घटनाओं से अपने पास के और दूर के पड़ोसियों को आतंकित रखता है।

सांगे ने कहा, "तिब्बतियों के पास यह मानने की हर वजह है कि चीन असल में तिब्बत को चाहता है, तिब्बती जनता को नहीं।" अगर ऐसा नहीं है तो चीन "एक देश, दो विधान" के हांगकांग और मकाऊ मॉडल का इस्तेमाल करते हुए तिब्बतियों को तिब्बती बने रहने के लिए निर्णय लेने का अधिकार क्यों नहीं देता-अपनी संस्कृति और भाषा को बचाए रखने के लिए। इसकी जगह तो उन्हें चीनी कठोर कार्रवाई का शिकार होना पड़ रहा है, खासकर हाल में वर्ष २००८ में यह हुआ है। यहां तक कि चीन ने सांगे के चुनाव में बाधा डालने की कोशिश करते हुए नेपाल पर यह दबाव डाला कि वह वहां रह रहे निर्वासित तिब्बतियों को मतदान में हिस्सा लेने के लिए भारत जाने से रोके।

इसके विपरीत देखें तो भारत अति घृणा के शिकार आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बावजूद अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और जम्मू-कश्मीर में नियमित रूप से स्थानीय और राज्य सरकार के लिए नियमित रूप से चुनाव कराता रहा है। अब विवादित क्षेत्रों में भारत का नैतिक अधिकार मजबूत हुआ है क्योंकि वहां के लोगों को अपनी आवाज प्रकट करने का मंच मिला है।

तिब्बती लोग चीन के साथ एक स्वीकार्य हल पर पहुंचे इसके लिए भारत को भी मदद करनी चाहिए। सांगे ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत से यह कहा है कि वह भारत की जमीन पर रहने वाले १,२०,००० तिब्बती शरणार्थियों का फायदा उठाते हुए तिब्बत में वास्तविक स्वायत्तता की बात उठाए और अपने और चीन के बीच दूरी बढ़ाना शुरू करे। ताकि एक अलग तरह का बफर फिर से तैयार हो सके। लेकिन भारत दलाई लामा और उनके अनुयायिओं को शरण देने पर चिंता में ही है। उसने एक तरह के बेतुका प्रोटोकॉल दुविधा की स्थिति तैयार करते हुए चीन को यह तय करने की छूट दी है कि वह आध्यात्मिक नेता से किस प्रकृति का और किस हद का संपर्क करेगा। उसने तिब्बती विरोध प्रदर्शनकारियों को सलाखों के पीछे डाला है ताकि वे चीनी आगंतुकों के लिए कोई मुसीबत न पैदा कर सकें। भारतीय पुलिस ने अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे तिब्बतियों के मुकाबले चीनी ओलंपिक मशाल को ज्यादा सम्मान दिया था। यह एक लोकतंत्र की बात है।

कुछ लोगों का तर्क है कि भारत को "तिब्बत कार्ड" खेलना चाहिए, लेकिन तिब्बती कोई कार्ड नहीं हैं-वे ऐसे लोग हैं जिनका लंबा इतिहास रहा है और जो लगातार चीन द्वारा दमन के शिकार हैं। चीनी शासन के खिलाफ ११७ तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है इससे ज्यादा दर्द की इंतहा और क्या हो सकती है? क्या भारत को इन तनावपूर्ण समय के मुताबिक अपने राजनय में बदलाव लाना चाहिए? भारत ने तिब्बत पर अपने अधिकार को पूरी तरह से छोड़ दिया है और उस पर चीन की संप्रुभता को स्वीकार कर लिया है ताकि उपनिवेशवाद के बाद के दौर में एकजुटता बनी रही और भारत को इसके बदले कुछ नहीं मिला है।

इसके बाद भारत ने "एक चीन" की नीति स्वीकार की और इसके बदले में उसे असल में "एक भारत" की नीति नहीं मिल पाई। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत लगातार रक्षात्मक रवैया अपनाता रहा है, और कभी-कभी बस बयानों के प्रारूप में ही थोड़ी से राजनयिक आक्रामकता दिखती है।

क्या भारत फिर से तिब्बत मसले को अपने हाथ में ले सकता है-सांकेतिक रूप से ही सही? चीन ने तो कभी भी भारत के खिलाफ तिब्बत कार्ड खेलने में कोई हिचक नहीं दिखाई है-वह अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है और उसकी ६०,००० वर्ग किमी. जमीन पर अपना दावा करता है। इसके साथ ही उसने अक्साई चिन पर भारतीय दावे को खारिज किया है जैसा कि पिछले साल हमने देखा है, अपने नए ई-पासपोर्ट में उसने इस इलाके को अपना हिस्सा दिखाया है। भारत ने जवाबी नक्शे के साथ वीजा जारी कर इसका प्रतिकार किया। वर्ष २०१० में प्रधानमंत्री वेन च्या पाओ की भारत यात्रा से पहले शिनहुआ ने दोनों देशों की सीमा को १,६०० किमी. लंबा बताया, जिस पर भारतीय राजदूत को यह कहने पर मजबूर

होना पड़ा कि सीमा ३,४८८ किमी. लंबी है। यह मानचित्र युद्ध एक साइड शो की तरह ही होना चाहिए और इसे भारतीय नीति का मुख्य आधार नहीं बनाना चाहिए। चीन के साथ सीमा विवाद में तिब्बत मुख्य मसला है। चीन को इसका असल हल निकालना चाहिए और इसके लिए तिब्बतियों की स्वायत्तता की मांग को तत्काल पूरा करना चाहिए। वर्ष २००२-२०१० के बीच हुई नौ दौर की वार्ता अब ठप पड़ गई है क्योंकि इसमें प्रगति से निराश दलाई लामा के दूतों ने इस्तीफा दे दिया है। चीनियों ने अब यह धमकी देनी शुरू की है कि वे तिब्बतियों का अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लेंगे, जिससे उनके स्वायत्तता मांगने का आधार ही खत्म हो जाए।

चीन ने दलाई लामा की "मध्यम मार्ग नीति" को स्वीकार नहीं किया है और वह जमीनी स्तर पर जनसांख्यिकीय बदलाव कर रहा है। तनाव चरम पर है क्योंकि चीनी लोग शीर्ष नौकरियों पर काबिज हो रहे हैं, जबकि सरकार वहां की प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध दोहन कर रही है। खबर है कि तिब्बती नोमैड को जबरन उनके परंपरागत जगह से कहीं और बसाया जा रहा है और दलाई लामा की तस्वीरों को लगातार अपमानित किया जा रहा है। वर्षों तक एकांगी सोच वाली सोशल इंजीनियरिंग और सांस्कृतिक दमन की वजह से ही आत्मदाह का युग शुरू हुआ है। भारत को अपने राजनय में बदलाव लाने की सैकड़ों वजहें हैं-चीन ने भारत के मुख्यत हितों के प्रति जरा भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई है, उसने सीमा वार्ताओं के दौरान दिए गए वचनों को कई बार तोड़ा है, उसने कई अंतरराष्ट्रीय क्लबों में भारत के "उभार" का कड़ा विरोध किया है, उसने अपने ही दम पर पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बना दिया है और संयुक्त राष्ट्र में बार-बार पाकिस्तान के आतंकी कृत्य का बचाव करता रहा है।

यह तर्क मैं इसलिए नहीं दे रही कि अनावश्यक तनाव बढ़े क्योंकि जमीनी स्तर पर भारत की अपनी कई सीमाएं हैं। लेकिन चीनी संवेदनशीलता को चोट पहुंचने के डर से जिस तरह से सांस्थानिक संकोच का प्रदर्शन किया जाता है हम उसे भी बढ़ावा नहीं दे सकते। इन दोनों के बीच संतुलन बनाने से ही कुछ मदद मिल सकती है।

(लेखिका वाशिंगटन डीसी में रहने वाली एक विश्लेषक हैं)

व्यापार, सीमा और जल के मसले पर भारत को सिर्फ आश्वासन देता है चीन

(दि इकनॉमिक टाइम्स, २६ मई)

ब्रह्मा चेलानी

तमाम प्रचार और शोर-शराबे के बीच भारत-चीन के बीच बैठक एक परिचित रेखा के इर्द-गिर्द ही चलती है: भारत काफी मेहनत से अपनी चिंताओं को आगे बढ़ाता है, खासकर नियंत्रण रेखा को साफ करने की चीन की अनिच्छा पर, एकतरफा व्यापारिक रिश्ते पर, पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की गतिविधियों पर और कई देशों के बीच बहने वाली नदियों पर अपारदर्शी तरीके से चल रही चीनी परियोजनाओं पर। चीनी पक्ष दोस्ती और सहयोग के बारे में पुराने तरीके से दिखावटी पवित्रता के साथ अपनी प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अगले सम्मेलन में जब भारत इसी भावना के साथ आता है, तब तक इसे तेजी से भुला दिया जाता है।

इस बीच व्यापारिक रुख और ज्यादा असमान हो गया है, चीन ने सीमा पार तक बहने वाली नदियों पर नए बांधों को उद्घाटन किया है, पाक अधिकृत कश्मीर में अपने सामरिक पदचिह्न और फैला लिए हैं और भारत पर दबाव बनाने के लिए चीनी सैनिकों द्वारा प्रायोजित घटनाएं बढ़ गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही २०१० में प्रधानमंत्री वेन च्यापाओ के नई दिल्ली दौरे और हाल में संपन्न ली किचियांग के दौरे के बीच बिल्कुल यही हुआ है।

असंतुलित व्यापार

बढ़ते व्यापारिक असमानता का ही उदाहरण लें। ली की यात्रा के बाद जो संयुक्त बयान जारी किया गया उसमें वायदा किया गया है, "व्यापारिक असंतुलन को दूर करने के लिए उपाय किए जाएंगे।" लेकिन जब वेन आए थे तब भी चीन ने बराबरी का मौका देने के लिए इसी तरह का वायदा किया था कि, "भारत का व्यापार घाटा कम करने के लिए चीन को ज्यादा भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे।" लेकिन इसके बाद चीन का व्यापार अधिशेष तब से और बढ़ा ही है और भारत के चालू खाते के घाटे में भारी बढ़त हुई है। वर्ष २०१० में शुरू हुए व्यापारिक वार्ताओं का नतीजा कुछ खास नहीं रहा है, जिससे चीन द्वारा अपना माल पाट देने से भारत को राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम ही है।

इस भरोसे के साथ कि भारत विश्व व्यापार संगठन में एंटी डंपिंग के मामले दर्ज करने के अलावा और कुछ खास नहीं कर पाएगा, चीन ने लगातार व्यवस्थित तरीके से भारतीय विनिर्माण की जड़ें खोदने का काम किया है। इसके अलावा यह अब भी बड़े पैमाने पर भारत से कच्चे माल का आयात करता है और यहां तैयार माल निर्यात करता है। उसने इस विकृत रुख को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए एक नया तरीका भी निकाला है, वह अपने बैंकों के द्वारा नकदी की तंगी से जूझ रही भारतीय कंपनियों को कर्ज दिलाता है और यह इस शर्त पर दिया जाता है कि वे चीनी कंपनियों से साजो-सामान खरीदेंगे या उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति करेंगी। अब जरा विवादित क्षेत्र पीओके में चीन के बढ़ते सामरिक हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय आग्रह पर चीन की प्रतिक्रिया देखें। ली भारत से सीधे अपने "सदाबहार दोस्त" पाकिस्तान के दौरे पर गए और उन्होंने पीओके के रास्ते एक आर्थिक गलियारा बनाने के लिए समझौते पर दस्तखत किए। इन परियोजनाओं की रक्षा के लिए चीन ने शियाओं की बहुलता वाले विद्रोहग्रस्त क्षेत्र गिलगित-बलूचिस्तान में अपने सैनिक तैनात किए हैं जिसका नतीजा यह हुआ है कि अब भारत को जम्मू-कश्मीर के दोनों बगल अब चीनी सैनिकों का मुकाबला करना पड़ सकता है, जबकि कश्मीर का करीब २० फीसदी हिस्सा चीन ने पहले ही हड़प लिया है।

इसके विपरीत चीन ने भारत की पीओके के बारे में आपत्तियों को लापरवाही दिखाते हुए नजरअंदाज किया है, खासकर जब भारत के ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने दक्षिण चीन सागर के दो भंडारों में से तेल निकालने के लिए पेट्रो वियतनाम से समझौता किया, उसके बाद भारी राजनयिक दबाव बनाने के लिए चीन ने ऐसा किया है। चीन ने वहां "किसी भी तरह के एकतरफा अन्वेषण गतिविधि" के लिए भारत को चेतावनी दी। इसके बाद पेट्रो वियतनाम को लाखों डॉलर की एक्जिट फीस चुकाते हुए अचानक

ओएनजीसी २०११ में पहले भंडार से और २०१२ में दूसरे भंडार के अन्वेषण कार्य से बाहर हो गया। विवादित जल वाली नदियां भारत-चीन संबंधों के बीच एक प्रमुख सुरक्षा मसला बन कर उभरी हैं।

"चीन ने साफतौर पर संकेत दिया है कि वह सीमा विवाद को हल करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा को आधार नहीं मानेगा"

लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरह ही ली ने भी मनमोहन सिंह के इस अनुरोध को कोई तवज्जो नहीं दिया है कि बांध निर्माण पर पारदर्शिता को संस्थागत रूप देने के लिए जल सहयोग को सिर्फ आंकड़ों की साझेदारी से कहीं आगे बढ़ाया जाए। चीन करीब एक दर्जन देशों के लिए जल का स्रोत है। लेकिन सीमा पार तक बहने वाली नदियों पर चीन की री-इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा जोखिम भारत के लिए ही है क्योंकि चीनी क्षेत्र से बाहर आने वाले जल का करीब आधा हिस्सा भारत में ही आता है। लेकिन चीन ने साझी नदियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने के लिए कोई समझौता करने या कई देशों की सरकारों का एक संस्थान बनाने के चीनी प्रस्ताव को लगातार ठुकराया है।

तीन दशक से भी ज्यादा समय से भारत सीमा के मसलों पर चीन के साथ बेनतीजा और कभी न खत्म होने वाले दौर की वार्ताओं में लगा रहा है जो कि आधुनिक इतिहास में किन्हीं दो देशों के बीच वार्ता की सबसे लंबी और सबसे बांझ प्रक्रिया साबित हुई है। चीन ने न केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को स्पष्ट करने की प्रक्रिया को पटरी से उतारा है, बल्कि उसने साफतौर से यह संकेत दिया है कि वह सीमा विवाद के निपटारे के लिए एलएसी को आधार नहीं मानेगा। जब वेन २०१० में भारत आए थे तो उन्होंने सीमा मसले पर सख्त संदेश दिया था-कि इस "मसले को हल करना इतना आसान नहीं है" और किसी भी तरह से इसमें "काफी लंबा समय लग सकता है।" तैयार भाषण में इस तरह की टिप्पणी असल में सार्वजनिक तौर पर उस 'दृढ़ प्रतिबद्धता' को धता बताना ही था जो कुछ घंटों पहले ही संयुक्त बयान में सीमा विवाद को 'पहले की तिथि से' हल करने के लिए जताई गई थी। चीन के पक्ष में झुके दिख रहे नवीनतम संयुक्त बयान में वास्तव में 'पहले की तिथि' वाले संदर्भ को ही हटा दिया गया है। यह तथ्य कि ली की यात्रा से पहले चीनी सैनिकों के लद्दाख में १६ किलोमीटर भीतर तक घुस गए, इस बात पर मुहर लगाता है कि चीन न तो एलएसी को स्पष्ट कर और न ही सीमा पर कोई निपटार करते हुए भारत पर लगातार दबाव बनाए रखना चाहता है। चीन ने इसके पहले भी सीमा वार्ताओं पर गठित संयुक्त कार्य समूह को झटका दिया है, वर्ष २००१ के अपने इस वायदे से पीछे हटते हुए कि वह पूर्वी और पश्चिमी सेक्टर भारत से नक्शों का आदान-प्रदान करेगा। अरुणाचल और कश्मीर कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अब वह तथाकथित विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) के नेतृत्व वाले संयुक्त कार्य समूह के बदलाव प्रणाली को बाधित करना चाहता है।

फायदा उठाने की भाषा

लद्दाख के दुस्साहसी घुसपैठ से हिल चुके भारत के पास पूरा अधिकार है कि वह चुपच. ाप चीन के एकतरफा व्यापार सुविधाओं और द्विपक्षीय राजनीतिक एवं सैन्य आदान-प्रदान को सीमा विवाद के मसले पर भारी प्रगति से जोड़े। लेकिन इस अवसर को पूरी तरह से गंवा दिया गया। उदाहरण के लिए संयुक्त बयान में विशेष प्रतिनिधियों के बीच दशक से भी ज्यादा समय से चल रही सीमा वार्ता पर हास्यास्पद तरीके से "संतुष्टि" जाहिर किया गया है और उन्हें "बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए" प्रोत्साहित किया गया है। यह रवैया भारत को उलझाए रखने की चीनी खेल को और मजबूती ही प्रदान करता है।

हालांकि, भारत ने चीन के "सीमा सुरक्षा सहयोग समझौते" के प्रारूप" के जवाब में सीमा पर झड़प और घुसपैठ को रोकने के लिए खास तौर से बनाए गए अपने एक समझौते का प्रस्ताव रख कर अच्छा काम किया है। चीनी समझौते के प्रारूप में हिमालय पर शांति और धीरज कायम रखने के नाम पर सीमा पर प्रतिरक्षा के लिए देर से ही सही भारत द्वारा हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाकर चालाकी से भारत को चीनी सेना के सामने झुक जाने के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश की गई है।

ली की यात्रा ने एक बार फिर से याद दिला दिया है कि भारत-चीन समिट में हाइप, झुकाव और रूढ़ोक्तियों को फिर से दोहराने के अलावा और कुछ खास नहीं होता। संवाद से पहले काबू करने की चीन की रणनीति से निपटने के लिए भारत को एक संगठित कार्य योजना अपनानी होगी जिसमें अपनी डराने वाली क्षमता को बढ़ाने के साथ ही मित्र देशों के साथ राजनयिक और सैन्य संबंध बढ़ाने के उपाय भी करने होंगे।

(लेखक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, दिल्ली में सामरिक अध्ययन के प्रोफेसर हैं और "वाटरः एशियाज न्यू बैटलग्राउंड" के लेखक हैं)

लद्दाख में चीनी दादागीरी - भारत का सही जवाब क्या हो ?

नई तिब्बत नीति के लिए एक सही मौका

- विजय क्रान्ति

विजय क्रान्ति पिछले चालीस साल से वह तिब्बत की स्थिति और भारत-चीन संबंधों का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। तिब्बती जीवन पर उनके विस्तृत फोटोग्राफी अभियान ने पिछले नवंबर में ४० साल पूरे किए। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके इंटरनेशनल टिबेट फोटो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत अगले दो साल में लगभग एक दर्जन देषों में तिब्बती जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर उनकी फोटो प्रदर्षनियां आयोजित की जाएंगी। ''बुद्धाज़ होम कमिंग'' शीर्षक वाले इस फेस्टिवल के पहले शो का उद्घाटन पिछले दिनों चंडीगढ़ में पंजाब विवि के फाईन आर्ट्स म्युज़ियम में पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल ने किया।

इन्हीं दिनों लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और उसके कारण खड़े हुए विवाद ने तिब्बत के सवाल को फिर से चर्चा का विषय बना दिया है। राष्ट्रीय समाचार के प्रधान संपादक नरेश गुप्ता ने भारत की तिब्बत और चीन नीति तथा इससे संबंधित अन्य विषयों पर विजय क्रान्ति से जो बातचीत की उसके कुछ अंश यहां प्रस्तुत हैं।

नरेश गुप्ता - लद्दाख में चीन के सैनिक भारतीय सीमा के भीतर तक न केवल घुस आए हैं, बल्कि वे वहां अपने तंबू गाड़कर बैठ गए हैं और कई दिन बीतने पर भी वे वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके हिसाब से चीन ऐसा क्यों कर रहा है?

विजय क्रान्ति - दुनिया में चीन एक ऐसा देश है जिसकी सांस्कृतिक विचारधारा में विस्तारवाद एक अभिन्न अंग की तरह जुड़ा हुआ है। आधुनिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना असल में ५६ देशों से बना हुआ है। चीनी हान जाति ने हमारे देखते-देखते मंचूरिया, भीतरी मंगोलिया, पूर्वी तुर्किस्तान (शिंजियांग) और तिब्बत जैसे ५५ देशों को हड़प कर नया चीन बना लिया है। अब उसकी नजर जापान, कंबोडिया, वियतनाम और भारत के सीमावर्ती इलाकों पर है।

नगु- लेकिन चीन ने कभी इन देशों मे जबरन घुसकर वहां बैठ जाने की हिम्मत नहीं की। भारत के साथ ही वह ऐसा क्यों कर रहा है?

विक्रा - युद्ध और कूटनीति के मामले में चीनियों अपना अलग चरित्र है। वे कभी भी ऐसे दुश्मन के साथ शरारत नहीं मोल लेते जो उनको मुंहतोड़ जवाब देने की मानसिकता रखता हो। भारत को वे शुरू से ही एक 'मूर्ख नेतृत्व वाला' और एक 'दब्बू' देश मानते आए हैं। नेहरू जी के जमाने से लेकर अटल जी तक के दौर में हर भारतीय सरकार ने उसकी इस समझ की पुष्टि ही की है। चीन सरकार ने हर बार गीदड़ भभकियां देकर अपनी बातें मनवा लीं और हर बार कुछ आगे बढ़ जाने के बाद वह फिर से नए दावे ठोकता आ रहा है। पहले उसने लद्दाख के अक्साई चिन पर कब्जा किया। उसके बाद अरुणांचल प्रदेश पर दावा जताया और अब वह असम और लद्दाख के उन हिस्सों पर दावा जता रहा है जिनके बारे में कभी बात ही नहीं की थी।

नगु- इस बार लद्दाख में चीन की ताजा कार्रवाई पर भारतीय प्रतिक्रिया के बारे में आपकी क्या राय है?

विक्रा - पिछले दो सप्ताह में भारत सरकार के रवैये ने भारतीय नेतृत्व के बारे में चीन की राय की फिर से पुष्टि की है। वे चीन की सैनिक कार्रवाई का सैनिक जवाब देने के बजाए कूटनीति लल्लो-चप्पो से समस्या को टालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चीनी घुसपैठ को एक हमलावर हरकत बताने और उसका ठोक कर जवाब देने के बजाए खुद भारतीय विदेशमंत्री और रक्षामंत्री यह कहकर उसे एक तार्किक कदम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होना स्वभाविक है क्योंकि नियंत्रण रेखा के बारे में दोनों देशों की राय अलग-अलग है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी भरी और कायर टिप्पणी आधुनिक कूटनीति या सैन्यनीति के इतिहास में कभी भी सुनने देखने में नहीं आयी। यह तो भारतीय नेतृत्व द्वारा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का निहायत शर्मनाक कदम है।

नगु- चीन सरकार इस कार्रवाई से क्या हासिल करना चाहती है?

विक्रा - इस कदम से चीन एकसाथ कई लक्ष्य हासिल करना चाहता है। एक तो यह कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा करने के मामले में भारत की सैन्य शक्ति और कूटनीतिक साहस का अनुमान लगाना चाहता है ताकि वह भारत के खिलाफ किसी संभावित बड़ी कार्रवाई की सही तैयारी कर सके। दूसरे, चीन की सरकार इस समय कई तरह के भयंकर तनावों से गुजर रही है। चीन का नया सत्ताधारी नेतृत्व इस समय ऐसे रास्ते खोज रहा है जिनसे वह अपनी जनता और प्रभावशाली सत्ता गुटों का ध्यान बंटाकर सत्ता पर अपना कब्जा कायम रख सके। कहने को तो चीन के सीमा विवाद और राजनीतिक विवाद कई देशों के साथ हैं। लेकिन

भारत अकेला ऐसा देश है जिसके खिलाफ एक सीमित युद्ध करके और अपनी 'जीत' दर्ज कराकर वह चीनी जनमत को आसानी से भरमा सकता है। इस सीमित युद्ध का निशाना अरुणाचल भी हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चीन पिछले कई साल से अरुणांचल प्रदेश को 'साऊथ तिब्बत' के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। उसकी दलील है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का है क्योंकि एक समय वह तिब्बत का हिस्सा था।

नगु- इस विवाद में भारत की तिब्बत नीति के बारे में आप क्या कहते हैं?

विक्रा - असल में भारत सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह भारत और चीन के रिश्ते में तिब्बत के महत्व को कभी सही नजरिए से देख ही नहीं पायी। तिब्बत के सवाल पर उसने कभी ऐसी नीति अपनाने की कोशिश भी नहीं की जो भारत के खिलाफ चीन की दादीगीरी पर नकेल लगा सके।

१९५१ में तिब्बत पर चीनी कब्जे का विरोध करने के बजाए उसकी ओर से आंख मूंदे रखने का परिणाम यह हुआ है कि ६२ साल के इस दौर में चीन ने तिब्बत को एक फौजी किले में बदल लिया है। जिस ४००० किमी लंबी भारत-तिब्बत सीमा के एक इंच हिस्से पर भी हजारों सालों से कभी भारत-चीन सीमा नहीं रही, उसी तिब्बती सीमा के पार से चीन भारत के नक्सलवादियों, उत्तर-पूर्वी भारत के भारत विरोधी अलगाववादी संगठनों और भारत विरोधी आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने, हथियार सप्लाई करने और शरण देने के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। तिब्बत की भूमि का इस्तेमाल करके चीन लगातार भारत को घेरने में लगा हुआ है। आज उसी तिब्बती भूमि से अपनी सैनिक तैयारी करके चीनी सेना लद्दाख में घुस आयी है। चीन की नीति हमेशा दूसरे की जमीन पर दावा जताकर अपनी जमीन को विवाद से मुक्त रखने की रही है।

नगु- आपने कहा कि तिब्बत की भूमि का इस्तेमाल करके चीन भारत को घेरने में लगा हुआ है। इसपर कुछ विस्तार से बताएंगे?

विक्रा - पहला तो यह कि तिब्बत पर कब्जा जमाने के बाद पिछले ६२ साल में चीन ने न सिर्फ तिब्बत में सैनिक छावनियों, हवाई अड्डों, परमाणु अस्त्रों और रेलवे तथा सड़कों का जाल बिछा दिया है बल्कि भारत की पूरी सीमा के साथ-साथ भारी सैनिक छावनियां बना डाली हैं। तिब्बत पर चीनी कब्जे के कारण पाकिस्तान, नेपाल और भूटान के साथ भी उसकी सीमा मिल गई है। पाकिस्तान की सहमति से चीन ने तिब्बत से अरब सागर तक अपना सड़क संपर्क बना लिया है। खाड़ी के प्रवेश द्वार पर ग्वादर में पाकिस्तानी नौसैनिक अड्डा बनाने के बाद अब उसके संचालन का ठेका भी चीन को मिल गया है। अब चीन सरकार तिब्बत से ग्वादर तक रेलवे लाइन बनाने जा रही है। नेपाल में भी विकास सहायता के नाम पर उसने तिब्बत से लेकर भारत की सीमा तक सड़कों का ऐसा नेटवर्क बना लिया है जिसका इस्तेमाल करके वह भारत के बिहार, उत्तराखंड और बंगाल प्रांतों तक अपनी सेना को ला सकता है।

म्यांमार में वहां की सरकार की मदद से उसने बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर ली है। यहां तक कि भारत के अंडमान-निकोबार नौसैनिक अड्डे से तीस मील दूर अपनी चौकी बना ली है। भारत सरकार की नासमझी की वजह से चीन ने श्रीलंका के लिए हंबनटोटा में नौसैनिक बंदरगाह विकसित करके भारतीय नौसेना के लिए नया खतरा पैदा कर दिया है।

भारत के भीतर सबसे खतरनाक चीनी कदम नक्सवादियों को शह देने का है। उसने भारतीय माओवादियों को हथियार और ट्रेनिंग देकर नेपाल में पशुपति से लेकर आंध्र में तिरुपति तक ऐसा भयंकर नक्सल गलियारा खड़ा कर दिया है जिसे मैं 'ग्रेट नक्सल वॉल ऑफ चायना' कहता हूं। बंगलादेश में गहरी पैठ जमाकर उसने दक्षिण-पूर्वी नेपाल और बंगलादेश के बीच ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि नेपाली और भारतीय माओवादियों की मदद से वह भारत के सात उत्तर-पूर्वी राज्यों को शेष भारत से काटने के लिए कभी भी कदम उठा सकता है। उस हालत में माओवादियों की 'ग्रेट नक्सल वॉल ऑफ चायना' भारतीय सुरक्षा सेनाओं को उत्तर-पूर्व की ओर जाने से रोक सकती है। और यह सब सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है कि तिब्बत पर चीन का गैरकानूनी कब्जा बरकरार है।

नगु- ऐसे में भारत को तिब्बत के सवाल पर क्या नीति अपनानी चाहिए?

विक्रा - मुझे लगता है कि लद्दाख में चीन ने ऐसी सैनिक कार्रवाई करके भारत सरकार को एक बहुत अच्छा और तार्किक अवसर दे दिया है कि वह तिब्बत पर अपनी नीति को नए सिरे से परिभाषित करे। अब दुनिया को यह बताना जरूरी हो गया है कि लद्दाख में विवादित सीमा के दोनों ओर भारत और तिब्बत की जमीन है न कि चीन की। तिब्बत पर जबरन और गैरकानूनी कब्जा जमाकर वह लद्दाख या अरुणांचल प्रदेश में तिब्बत के नाम पर अपने दावे नहीं ठोक सकता।

मैं इस राय का हूं कि अब वक्त आ गया है जब भारत सरकार चीन को खुलकर यह बता दे कि तिब्बत पर उसका कब्जा गैरकानूनी है। इस तरह के गैरकानूनी कब्जे को आधार बनाकर किसी भी भारतीय इलाके पर दावा जताना न तो अंतर्राष्ट्रीय कानून से तर्कसंगत है और न नैतिक तौर पर। भारत के ऐसी नीति अपनाने से चीन को अपने आक्रामक तेवर छोड़कर तुरंत बचाव की मुद्रा अपनानी पड़ेगी। चीन जैसे अक्खड़ देश पर नकेल कसने के लिए ऐसी ही नीति की जरूरत है। ऐसा कदम उठाकर हम न केवल भारत के हितों को सुरक्षित करेंगे बल्कि तिब्बत की जनता के प्रति हम अपनी उस नैतिक जिम्मेदारी को भी पूरा करेंगे जिसे दुर्भाग्य से हम बरसों से भुलाते आए हैं।

नगु - क्या ऐसे कदम से चीन भड़क नहीं जाएगा ? भारत-चीन संबंध भी तो बिगड़ सकते हैं ?

विक्रा - पिछले साठ साल से चीन सरकार भारत के प्रति जो रवैया अपनाए हुए है उसे देखते हुए कौन कहेगा कि भारत-चीन रिश्ते मिठास भरे हैं? या कि भारत के प्रति चीन दोस्ताना रवैया रखता है? कभी अरुणांचल तो कभी असम, कभी लद्दाख तो कभी कश्मीर, कभी नेपाली माओवादियों के माध्यम से तो कभी भारत के माओवादी और दूसरे आतंकवादी संगठनों के माध्यम से, कभी पाकिस्तान को राजनीति समर्थन देकर तो कभी उसे परमाणु हथियार बनाने की सुविधा देकर चीन ने लगातार यह दिखा दिया है कि भारत के खिलाफ उसका खतरनाक अभियान जारी है। पिछले छह दशक से चीन के सामने दब्बू नीति अपनाकर भारत देख चुका है कि चीन के सामने आप जितनी शराफत और रिआयत की नीति अपनाएंगे, वह इसे आपकी कमजोरी समझता है और एक कदम और आगे बढ़कर आपकी गर्दन पर सवार होने की कोशिश करता है। भारत को समझ लेना चाहिए कि चीन की सबसे ज्यादा दुखती रग तिब्बत है। नैतिकता और कूटनीति दोनों का तकाज़ा है कि भारत अपनी पुरानी गलती को सुधारते हुए तिब्बत के सवाल पर आक्रामक और आत्मसम्मान वाली नीति अपनाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सदियों से चीन और भारत के बीच एक आजाद तिब्बत की मौजूदगी भारत की सुरक्षा की सबसे भरोसेमंद गारंटी रही है। ऐसे तुरुप के पत्ते को कूड़ेदान में नहीं, हाथ में रखना चाहिए।

माय लैंड ऐंड माय पीपल

(दलाई लामा की आत्मकथा)

समीक्षकः ऐशबी हार्डेस्टी

चौदहवें दलाई लामा की आत्मकथा माय लैंड ऐंड माय पीपलः दि ओरिजिनल ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज हाइनेस द दलाई लामा १९६२ में प्रकाशित हुई थी और यह तब तक के दलाई लामा के जीवन के बारे में विस्तार से बताती है। इसमें वह १९३५ में दोखम के तक्तसर गांव में अपने पुनर्जन्म को याद करते हैं, सिर्फ दो साल की उम्र में जब उन्हें १४वें दलाई लामा के रूप में पहचाना गया था, इसके बाद उनका केंद्रीय तिब्बत के शहर ल्हासा जाना, १९५० के दशक में चीन जनवादी गणतंत्र का हमला और कब्जा और १९५९ में उनके तिब्बत से आकर भारत में निर्वासित जीवन बिताने तक का पूरा विवरण है। यह किताब सरल लेकिन आग्रही शैली में प्रभावी तरीके से इस कहानी की नाटकीयता को दर्शाती है और यह तिब्बती जनता और उनके अधिकारों के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण लेकिन जटिल तस्वीर पेश करती है।

अपनी आत्मकथा के अंतिम पेजों में चौदहवें दलाई लामा अपने जीवन की कहानी बताने के पीछे के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। वह लिखते हैंः "अपने लोगों के विनाश और उन्होंने जो कुछ भोगा है उसको देखते हुए निर्वासन में मैंने अपने को उस कार्य में समर्पित कर दिया जो एकमात्र कार्य मैं कर सकता था...इस किताब के द्वारा दुनिया को यह याद दिलाना कि तिब्बत में क्या हुआ है और क्या हो रहा है" (१८७)। वास्तव में इस बयान के पहले वाले पेजों में दलाई लामा १९५० के दशक में चीन जनवादी गणतंत्र (पीआरसी) द्वारा तिब्बत पर कब्जे और वहां के विनाश की गाथा ऐसे महत्वपूर्ण और मर्मस्पर्शी तरीके से बताते हैं कि पाठक तिब्बती जनता एवं उनकी खोई हुई भूमि के अधिकारों के साथ सहानुभूति रखने और चीन के कार्यों की आलोचना

करने से बच नहीं सकता। लेकिन इस स्मृति लेख में, जो पहली बार १९६२ में प्रकाशित हुआ और तिब्बती से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, दलाई लामा चीन की एक सामान्य राजनीतिक खंडन या उसकी आलोचना से ज्यादा कुछ बताते हैं। वह तिब्बती धार्मिक और राजनीतिक सोसाइटियों के साथ मिलकर काम करने और उस असाधारण समय में लिए गए निर्णयों के बारे में आश्चर्यजनक रूप से सूक्ष्म और ईमानदार दृष्टिकोण पेश करते हैं। ऐसा करते हुए दलाई लामा इस जीवन के द्वारा

अपने जन्मभूमि, वहां के लोगों, धर्म के आग्रह को तो पेश करते ही हैं, साथ ही ऐसे पाठकों के लिए तिब्बती बौद्ध धर्म का अमूल्य तस्वीर पेश करते हैं जो उससे परिचित नहीं होंगे या जो यह नहीं जानते होंगे कि इसका ऐतिहासिक और वर्तमान समय में चीन और दुनिया के साथ कैसा गूढ़ रिश्ता है।

दलाई लामा अपने ल्हामो ढोनड्रुप के रूप में बिताए गए समय और पारिवारिक गांव और अपने परिवार के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी देते हैं। असल में दो साल की उम्र में चौदहवें दलाई लामा के रूप में पहचाने जाने से पहले उनका यही नाम था। वह केंद्रीय तिब्बत में ल्हासा पर शासन करने के लिए बने थे, लेकिन उनका जन्म पूर्वोत्तर तिब्बत के जिले दोखम में स्थित तक्तसर गांव के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। यह गांव तब चीन के धर्मनिरपेक्ष शासन के तहत आता था, लेकिन यह दलाई लामा के आध्यात्मिक और लौकिक शासन से निर्देशित होता था (१)। उन्होंने अपने परिवार को "बड़ा और गरीब" लेकिन "खुश एवं संतुष्ट" बताया है (५-६)। वह इस संतुष्टि का श्रेय तेरहवें दलाई लामा को देते हैं जिन्होंने "तिब्बत का दर्जा एक स्वाधीन देश के रूप में स्पष्ट और परिभाषित किया था और लोगों की बेहतरी की दिशा में बहुत कामयाबी हासिल की थी" (६)।

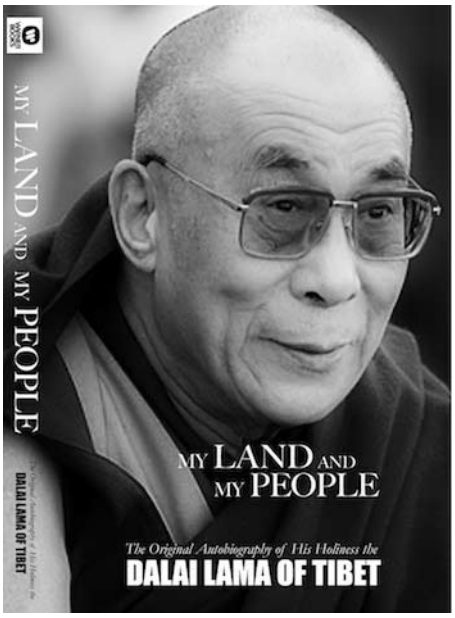

इस टिप्पणी से चौदहवें दलाई लामा के आगे के जीवन के बारे में कुछ पूर्वानुमान मिलता है: १६ वर्ष की अवस्था में १९४९ में जब उन्हें औपचारिक तौर पर पूर्ण लौकिक सत्ता सौंपी गई तो उनके अस्तित्व को इन्हीं दो लक्ष्यों ने परिभाषित किया। वर्ष १९३७ में जन्म के दो साल बाद और तेरहवें दलाई लामा की मृत्यु के चार साल बाद इस छोटे बच्चे को चौदहवां दलाई लामा घोषित किया गया और उनका नाम बदलकर जेतसुन जामफेल गवांग लोबसांग येशी तेनजिन ग्यात्सो रखा गया। उनका आध्यात्मिक प्रशिक्षण शुरू करने के लिए उन्हें ल्हासा ले जाया गया। कठिन शिक्षा प्रक्रिया का वर्णन करने के बाद, ल्हासा में अपने जीवन और "हमारे खुशहाली के दिनों में हमारे लोगों के जीवन" (चीन के आक्रमण से पहले का जीवन), दलाई लामा की आगे की कहानी में चीन सरकार के साथ तिब्बत के ऐतिहासिक रिश्तों का वर्णन है। यहां से दलाई लामा अपनी कहानी में एक मोड़ देते हैं और अचानक विदेशी संबंध और अंतरराष्ट्रीय राजनय में अपने क्रैश कोर्स, भारत एवं चीन के अपने दौरे, तिब्बत की स्वाधीनता के लिए माओत्से तुंग एवं नेहरू जैसे नेताओं से मुलाकात और इस तरह के प्रयास विफल रहने के बाद चीनी कम्युनिस्ट शासन की बर्बादी से तिब्बती बौद्ध धर्म को बचाने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करते हैं। यह वृत्तांत चीनियों और अपनी जनता के टकराते हितों के खिलाफ खौफनाक लड़ाई के बीच तिब्बत से निकल कर निर्वासित के रूप में भारत आने के साथ खत्म होता है।

इस कथा में नाटकीयता तो है ही, यह वृत्तांत कई वजहों से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। पहला, यह वृत्तांत २०वीं सदी के सबसे सम्मानित नेताओं के जटिल मानस और गूढ़ विचारों की बेशकीमती झलक पेश करता है। ऐसा करने में दलाई लामा कई आश्चर्यजनक विचार पेश करते हैं और उनके यह चिंतन और विचार उन्हें तिब्बती स्वायत्तता के शीर्ष हस्ती के रूप में पेश करते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा तिब्बत की स्वाधीनता के सवाल को उठाने की अनिच्छा की चर्चा करते हुए दलाई लामा एक अप्रत्याशित तरीके से इस राजनयिक विफलता की व्याख्या करते हैं। ब्रिटेन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की गलतियों की चर्चा करने के साथ ही वह लिखते हैं: "निश्चित रूप से अब जब मैं अपने पिछले इतिहास की ओर देखता हूं तो यह देखना सहज है कि किस तरह से हमारी अपनी नीतियों ने ही हमें इस हताशा की स्थिति में ला खड़ा किया है" (६५)। तिब्बत सरकार की यह आलोचना रोचक है क्योंकि यह न केवल तिब्बतियों को अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति के शिकार के रूप में दिखाता है, बल्कि देश की स्वाधीनता खोने की आंशिक जिम्मेदारी भी उनके ऊपर डालता है। इसके परिणामस्वरूप तिब्बती स्वायत्तता के सबसे विवादास्पद और व्यापक तौर पर पहचाने जाने वाली हस्ती दलाई लामा, मेलविन गोल्डस्टीन या सेरिंग शाक्य जैसे विद्वानों की तूलना में तिब्बती इतिहास का ज्यादा जटिल दृष्टिकोण पेश करते हैं।

दलाई लामा फिर कम्युनिस्ट शासन के तहत होने वाले चीन के विकास के बारे में भी अप्रत्याशित रूप से संतुलित नजरिए का प्रदर्शन करते हैं। वह लिखते हैं: "चीन में करीब एक साल बिताने के बाद मेरी सामान्य धारणा यह बनी कि चीन में सक्षमता और भौतिक प्रगति हुई है, और वह परिहास रहित एकरूपता का धूसर धुंआ है जिसके द्वारा पुराने चीन की परंपरागत आकर्षण और शालीनता अक्सर आश्चर्यजनक और स्वागतयोग्य हरियाली जैसी चमकती है" (९५)। चीन के आधुनिकीकरण करने में चीन सरकार की खुली तारीफ और सराहना से झटका लगता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्वासित तिब्बती समुदाय के एक वर्ग के लिए यह परेशानी वाली बात है। फिर भी, यह इस बात पर और रोशनी डालता है कि दलाई लामा अपने देश की परिस्थिति को आदर्शवादी चश्मे और आसान श्रेणियों के आधार पर देखने से इनकार करते हैं।

दलाई लामा के मानस पर आंतरिक रोशनी के अलावा उनका यह वृत्तांत यह देखते हुए ऐतिहासिक रूप से अमूल्य है कि यह किन परिस्थितियों में लिखी गई है और आज विश्व राजनीति में दलाई लामा की क्या स्थिति है। जब पहली बार १९६२ में इसका प्रकाशन किया गया था तो दुनिया के ज्यादातर लोग तिब्बती जनता और निर्वासित तिब्बतियों के संघर्ष के बारे में बहुत कम जानते थे। यह किताब अपने साधारण लेकिन आग्रही शैली और शांति के सार्वभौमिक संदेश की वजह से तिब्बत के बारे में ऐतिहासिक उपेक्षा को खत्म करता है और अंततः उसे बड़े स्तर पर विश्व मंच पर पहुंचा देता है। इस आत्मकथा के बारे में दलाई लामा तिब्बती जनता और तिब्बत देश के बारे में एक सहानुभूतिपूर्ण लेकिन जटिल तस्वीर पेश करते हैं। यह तिब्बती ऐतिहासिक विद्वता एक अनिवार्य कार्य है और तिब्बती जनता, उनके धर्म, उनके संघर्ष और उनके स्वाधीनता आंदोलन के बारे में पश्चिमी दुनिया में व्यापक समझ के लिए प्रेरित करने वाला कार्य है।